# राशन दुकानों से अब किराने का सामान भी मिलेगा

- मुख्यमंत्री पोषण मार्ट योजना शुरू करने की तैयारी
- मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी

**प्रशासनिक संवाददाता**

**भोपाल, 24 दिसंबर. आने वाले दिनों में राशन की दुकानें किराने की दुकान में भी तब्दील हो सकती हैं, जहां खाने-पीने का सामान तो मिलेगा ही, दैनिक उपयोग में काम आने वाली सामग्री भी मिल सकेगी. इसके लिये राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पोषण मार्ट योजना तैयार कर ली है, अब इस पर अमल किया जाएगा.**

यह जानकारी बुधवार को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी. उन्होंने इस दौरान विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया. राजपूत ने बताया कि राशन की दुकानों पर विविध पोषण सामग्री सहित दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उसे जन पोषण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. राशन दुकानों में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन लेने में हो रही दिक्कतों को लेकर मंत्री ने कहा कि यदि बुजुर्ग के परिवार का कोई भी सदस्य जिसे बुजुर्ग राशन लेने के लिये अधिग्रहित कर देंगे, उनको भी राशन देने की व्यवस्था की जाएगी, इसी तरह अंगूठे के निशान लगाने से पहचान की समस्या पर उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर हाथ के अंगूठे के साथ आंखों को स्कैन करके खाद्यान्न पर्ची को पीओएस मशीन से लिंक किया जाएगा. उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में ई-केवायसी के लिये चलाये गये अभियान में 35 लाख अपात्रों के नाम काटे गये हैं. राजपूत ने बताया कि प्रदेश में दो वर्ष में लगभग एक करोड़ 70 लाख से अधिक हितग्राहियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है. अब तक 4 करोड़ 97 लाख हितग्राहियों के ई-केवाईसी कराये जा चुके हैं।

इस तरह से अब तक लगभग 93 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण हो चुके हैं. बायोमेट्रिक के साथ-साथ फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों एवं दिव्यांगजनों सहित लगभग 15 लाख हितग्राहियों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है, साथ ही 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को जोड़कर पात्रता पर्ची जारी की गई है.

### अनाज भंडारण की रियल टाइम मॉनीटरिंग

राजपूत ने बताया कि वेयरहाउसिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नमी मापक, फ्यूमिगेशन एवं निरीक्षण से संबंधित तीन मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जिससे अनाज भंडारण की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है. किसान हित में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीदी की गई. लगभग 28 लाख किसानों से फसल खरीदी कर 51 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. गेहूं की खरीदी में 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया. उन्होंने बताया कि हमने 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया है, ये वादा पांच वर्ष के लिये किया था, लेकिन उससे पहले ही हम उससे भी अधिक तक पहुंच जाएंगे. उन्होंने बताया कि सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में राशन एवं गैस आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था किए जाने की कार्य योजना भी तैयार की गई है.

### 2028 तक शहरों में सभी घर में पाइप से पहुंचेगा एलपीजी

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी शहरों में घर-घर पाईप से एलपीजी पहुंचाया जाएगा, पहले वर्ष 2023 तक ये काम पूरा होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है. पाईप लाइन बिछाने का काम करने वाले वेंडरों की सुविधा के लिये सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया है.

# सतवास में अतिक्रमण हटाने पहुँचा प्रशासन, मचा बवाल

- पति-पत्नी ने किया आत्मदाह का प्रयास
- जेसीबी पर पथराव, कर्मचारियों को भागना पड़ा

**देवास / सतवास. 24 दिसंबर. सतवास नगर के वार्ड क्रमांक 5 में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात उस समय बेकाबू हो गए, जब कार्रवाई से आक्रोशित दंपती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना के बाद मौके पर भारी हंगामा हुआ और नगर परिषद की जेसीबी मशीन पर पथराव किया गया।**

हालात बिगड़ने पर तहसीलदार, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके से भागना पड़ा।

वार्ड क्रमांक 5 निवासी मोहनदास पिता रामदास बैरागी ने तहसीलदार कार्यालय में आवेदन देकर शिकायत की थी कि उनके पड़ोसी संतोष व्यास द्वारा सार्वजनिक नाली पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर लिया गया है, जिससे नाली जाम हो गई और पानी की निकासी बाधित हो रही है। बताया जा रहा है कि यह विवाद पिछले कई महीनों से चला आ रहा था। शिकायत के बाद एक दिन पूर्व मंगलवार को सतवास तहसीलदार अरविंद दिवाकर ने मौके का निरीक्षण किया था।

इस दौरान अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा तहसीलदार के साथ गाली-गलौज की भी बात सामने आई थी। इसके बाद बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बुधवार को तहसीलदार अरविंद दिवाकर राजस्व विभाग, नगर परिषद और पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे। टीम में कोटवार भी शामिल थे, जबकि मौके पर पुलिस बल की संख्या कम बताई जा रही है। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अतिक्रमण हटाए जा रहे मकान के मालिक संतोष व्यास और उनकी पत्नी जय श्री व्यास ने विरोध स्वरूप खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को बचाया और आग बुझाई।

# डीआरएम ने प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य का किया निरीक्षण

**भोपाल. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों के साथ व्यावरा-राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य का निरीक्षण किया. यह कार्य भोपाल-रामगंजमंडी नई रेल लाइन परियोजना से स्टेशन को जोड़ने के लिए किया जा रहा है.**

निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से जुड़े सभी संरक्षा पहलुओं का परीक्षण किया और यार्ड रिमॉडलिंग से संबंधित निर्धारित मानकों की जानकारी ली. उन्होंने स्टेशन मास्टर पैनल की कार्यप्रणाली का भी निरीक्षण किया, ताकि गाड़ी संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी या संरक्षा संबंधी कमी न रहे.

डीआरएम ने स्टेशन पर उपलब्ध मूलभूत यात्री सुविधाओं का भी अवलोकन किया. इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत व्यावरा-राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई. उन्होंने निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए. डीआरएम ने स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म और अन्य संरचनाओं का भी निरीक्षण किया. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय के अलावा वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता दिनेश कुमार कलाम और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

# नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार

## बजरंग दल ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा, महिदपुर रोड बंद

**नवभारत न्यूज़**

**महिदपुर, 24 दिसंबर. युवतियों से छेड़छाड़ के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता भी अपनी सक्रियता से मामलों को पकडक़र पुलिस के समक्ष पेश कर रहे हैं।**

ऐसा ही एक मामला महिदपुर रोड में 16 वर्षीय लडक़ी के साथ छेड़छाड़ का आया है। इसमें ऑटो चालक जुबेर मंसूरी को बजरंग दल ने पकड़ा। तनाव के बाद महिदपुर रोड बंद रहा। आरोपी लंबे समय से नाबालिग को कोचिंग भेजने के लिए ले जाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन से कुछ संदिग्ध वीडियो मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। इधर कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह आरोपी का जुलूस निकालने और उसका घर तोडऩे की मांग करते हुए नगर बंद करा दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी स्कूलों में लगे वाहनों में संदिग्ध ड्राइवरों को हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरोपी के पास से कुल 20 महिलाओं के वीडियो मिले हैं। जिनमें से 12 महिलाएं महिदपुर की हैं और 8 अन्य महिलाएं आसपास के क्षेत्रों की हैं।

### इनका कहना है

महिदपुररोड में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकडक़र सुबह न्यायालय के सक्षम पेश भी कर दिया है। इस मामले में जो भी सख्त कार्रवाई होगी हम करेंगे।

एसडीओपी

### हेड कांस्टेबल आत्महत्या मामला, महिला गिरफ्तार

**मैहर.** मैहर जिले के रामनगर थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रामदुलारे यादव को आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप में एक महिला अतिथि शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त 2025 की दोपहर हेड कांस्टेबल रामदुलारे यादव ने अपने शासकीय आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना स्थल से मिले सुसाइड नोट में मृतक ने महिला अतिथि शिक्षक कुंती बेलदार पर शादी के लिए दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना के बाद प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

# नारी सशक्तिकरण मिशन के लिए समिति का गठन

**प्रशासनिक संवाददाता**

**भोपाल, 24 दिसंबर. नारी सशक्तिकरण मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया है.**

समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गृह, परिवहन, खेल और युवा कल्याण, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, श्रम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, विधि और विधायी कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनसम्पर्क, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पर्यटन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु कल्याण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन सदस्य होंगे. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव महिला एवं बाल विकास को सदस्य-सचिव नामित किया गया है. समिति की बैठक 3 माह में एक बार की जायेगी. बैठक के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक आवश्यक होगा.

# 8 .65 लाख मतदाताओं को नोटिस

**भोपाल, 24 दिसंबर. विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद मप्र की मतदाता सूची की स्थिति स्पष्ट हो गई है. ड्राफ्ट के अनुसार मृत मतदाताओं की संख्या के मामले में जबलपुर जिला प्रदेश में सबसे आगे है, जबकि भोपाल और इंदौर में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं. एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने की स्थिति में बुरहानपुर जिला प्रमुख रूप से सामने आया है.**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार ड्राफ्ट सूची में प्रदेशभर से कुल 42 लाख 74 हजार मतदाता बाहर हुए हैं. इनमें 8 लाख 65 हजार 832 ऐसे मतदाता हैं, जिनसे आयोग संपर्क नहीं कर पाया. इन सभी को बुधवार से नोटिस जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज बीएलओ के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद उनका नाम पुन: जोड़ा जा सकेगा.

ड्राफ्ट के अनुसार मृत मतदाताओं में जबलपुर में 51 हजार 357, इंदौर में 43 हजार 741, सागर में 36 हजार 467, भोपाल में 33 हजार 791, धार में 27 हजार 943, ग्वालियर में 27 हजार 852 और उज्जैन में 27 हजार 851 नाम पाए गए हैं. प्रदेशभर में मृत श्रेणी के मतदाताओं की संख्या 8 लाख 46 हजार 184 है.

मतदाता शिफ्टिंग के मामलों में भोपाल 2 लाख 86 हजार 661 मतदाताओं के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा. इसके बाद इंदौर में 1 लाख 97 हजार 898, ग्वालियर में 1 लाख 48 हजार 273, जबलपुर में 1 लाख 15 हजार 437 और सागर में 80 हजार 901 मतदाता शिफ्ट पाए गए. सभी जिलों को मिलाकर कुल शिफ्टेड वोटर्स की संख्या 22 लाख 78 हजार 393 है. एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के नाम दर्ज होने के मामलों में बुरहानपुर में 23 हजार 594 वोटर्स के नाम पाए गए.

# छात्रों को प्रताड़ित करने वाली शिक्षिका निलंबित

**सागर, 24 दिसंबर. छात्रों को प्रताड़ित करने तथा अनुशासनहीनता के आरोप में सागर जिले की एक शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी के आदेशानुसार की गई है.**

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी सागर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय खिमलासा, विकासखंड खुरई, जिला सागर में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक दीपाली सिंघई को निलंबित किया गया है. बताया गया कि कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद सिंघई द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रताड़ित किया गया.

आरोप है कि शिक्षिका ने छात्रों को भड़काकर प्राचार्य एवं शिक्षकों के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अनुमति के नारे लगवाए, जाम लगवाया और उपद्रव कराया, जिससे संस्था तथा विभाग की छवि धूमिल हुई.

मामले के परीक्षण के उपरांत सिंघई प्रथम दृष्टया दोषी पाई गईं.

# एसआईआर में गंभीर अनियमितताओं का आरोप

## कांग्रेस ने जताई नाराज़गी

**विशेष संवाददाता**

**भोपाल,24 दिसंबर. मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे मतदाता अधिकारों पर सीधा हमला बताया.**

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्य कमलेश्वर पटेल ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.

सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एसआईआर के प्रथम चरण के बाद को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कई गंभीर खामियां हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्यापन के दौरान 5 करोड़ 31 लाख से अधिक मतदाताओं को गलत तरीके से 'नॉट मैपिंग' श्रेणी में डाल दिया गया, जबकि उनकी अलग सूची न तो मतदान केंद्रों पर चस्पा की गई और न ही वेबसाइट पर अपलोड की गई. उन्होंने यह भी कहा कि एएसडीआर सूची की मुद्रित प्रतियां न तो बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को दी गईं और न ही राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गईं, जिससे हटाए गए मतदाताओं की पहचान संभव नहीं हो पा रही है.

वर्मा ने एसआईआर के दौरान मतदान केंद्रों में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई नए बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त नहीं हैं, जिससे दावा-आपत्ति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस द्वारा उठाई गई आपत्तियों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो पार्टी संवैधानिक और न्यायिक रास्ता अपनाएगी.

# धोखाधड़ी के शिकार युवक को लौटाए 4 लाख 72 हजार रुपए

**धार, 24 दिसंबर. जिले में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के शिकार एक व्यक्ति की मेहनत की कमाई वापस दिलाई है. यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन की सतर्कता और एनसीआरपी पोर्टल की प्रभावशीलता को दर्शाती है.**

पुलिस के अनुसार फरियादी जावेद पिता जहीर, निवासी राजेन्द्र मार्ग धार ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. फरियादी ने बताया कि वह कुछ माह पूर्व सऊदी अरब से लौटा था और स्वयं का काम शुरू करने की इच्छा से एक परिचित के माध्यम से एक कंपनी में निवेश किया. उसे बताया गया कि प्रतिमाह आय होगी. इसके बाद फरियादी ने कंपनी में 5 लाख 7 हजार रुपए का निवेश किया.

कंपनी द्वारा उसे किताब स्कैन कर पीडीएफ बनाकर हेड ऑफिस भेजने का कार्य दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी बंद हो गई और कंपनी सार वेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी राजीव शर्मा भोपाल, डायरेक्टर, राज साधु फाइनेंस मैनेजर, अभिनव भटनागर सीओ, वरुण अग्रवाल और पुनीत गोयल स्टेट हेड के मोबाइल नंबर भी बंद आने लगे.

पत्रकार वार्ता | खेल व सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी

# डिफॉल्टर किसानों के लिये लाएंगे एकमुश्त समझौता योजना

**प्रशासनिक संवाददाता**

**भोपाल, 24 दिसंबर. प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिये राज्य सरकार एकमुश्त समझौता योजना लाने की तैयारी में है. इतना ही नहीं आर्थिक अनियमितताओं से प्रभावित किसानों को जांच अवधि में राहत देने की व्यवस्था के लिये न्याय योजना भी लाने की तैयारी की गई है. ये दोनों ही योजना शीघ्र ही कैबिनेट में पेश होगी, इससे डिफॉल्टर किसानों को खाद लेने में सुविधा मिलेगी.**

यह जानकारी बुधवार को सहकारिता एवं खेल व युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी. इस दौरान उन्होंने दोनों ही विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा भी पेश किया. सारंग ने कहा कि किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिये ऑनलाइन केसीसी आवेदन, एकीकृत साख सीमा तथा नकद-वस्तु ऋण की बाध्यता समाप्त करने जैसे सुधार भी किये जाएंगे. सभी पैक्स और ई-पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं और एसएमएस सूचना को अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कमजोर जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता देकर जीरो फीसदी ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. सारंग ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के मुताबिक राज्य की सहकारिता नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. जनवरी 2026 में आईबीपीएस के माध्यम से 2000 से अधिक पदों पर भर्ती एवं सतत प्रशिक्षण की योजना है. उन्होंने कहा कि सीपीपीपी मॉडल के विस्तार से सहकारिता में निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा.

### स्पोर्ट्स कोटा से प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर और 50 कांस्टेबल नियुक्त होंगे

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि मप्र पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा लागू कर प्रतिवर्ष 10 सब-इंस्पेक्टर एवं 50 कांस्टेबल की नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा. मुख्यमंत्री खेल अधोसंरचना विकास योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से इंडोर हॉल एवं आधुनिक खेल परिसरों का निर्माण प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने हेतु विदेश भेजा जा रहा है तथा विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं.

## पेज एक का शेष...

### आज दो लाख करोड़ के निवेश के लिये जमीन आवंटन होगा

'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। इससे प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी। अटलजी की जयंती पर आयोजित इस ग्रोथ समिट से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। निवेश से रोजगार - अटल संकल्प, उज्ज्वल मध्यप्रदेश की थीम पर आधारित इस समिट में विगत 2 वर्षों में प्रदेश में हुए औद्योगिक विस्तार, निवेश उपलब्धियों और रोजगार सृजन के वास्तविक परिणामों को सबके साथ साझा किया जाएगा। इस समिट से आने वाले वर्षों में विकास की नई दिशा भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के समग्र विकास के लिये उन्हें सीधे रोजगार और आजीविका से जोड़ने के लिए ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है।

इस समिट से नए औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर और प्लग-एंड-प्ले इकाइयों की शुरुआत से स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। समिट में भूमि-पूजन और लोकार्पण के साथ भूमि आवंटन और आशय-पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं संचालन करने वाले निवेशकों को सम्मानित किया जाएगा। समिट में युवाओं से संवाद भी किया जाएगा। संभाग स्तर पर औद्योगिक भूमि आवंटन से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी की जाएँगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

**उद्योग जगत की सहभागिता:** ग्रोथ समिट में देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गौतम सोलर, हीडलबर्ग सीमेंट, एलएनजे भीलवाड़ा समूह, जेके टायर, टोरेंट पावर, मैकेन फूड, एलिक्सर इंडस्ट्रीज, ग्रीनको, जुपिटर वैगन्स, डाबर इंडिया, वर्धमान समूह, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे प्रमुख औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

कार्यक्रम स्थल पर अटलजी के जीवन, विचारों और विकास दृष्टि पर आधारित विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में बीते 2 वर्षों में हुए औद्योगिक सुधारों, निवेश प्रयासों और रोजगार उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे मध्यप्रदेश की औद्योगिक यात्रा को एक ही स्थान पर देखा जा सकेगा।